speak first should be given a chance. So, let her speak. ...(*Interruptions*)... If you permit her to speak, only then she can speak. And then Dr. Alladi P. Rajkumar wants to raise the issue of drought in Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)...

RE. BIFURCATION OF EASTERN RAILWAY

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभापति महोदया, भारतीय रेलवे देश की एकता और एकजुटता का प्रतीक रही है और वह पूरे देश की जनता को जोड़ने का काम करती रही है लेकिन कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने जो अविवेकपूर्ण और अयुक्तिसंगत निर्णय लिया है, उससे उसने यह साबित कर दिया है कि वह अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के सामने देश के वृहत्तर हितों की कोई परवाह नहीं करती है ।

महोदया, मैं यह समझती हूं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की कैबिनेट के इस निर्णय का रेलवे की प्रशासनिक ऐफिशियेंसी के साथ कुछ लेना-देना नहीं है । इसके पीछे प्रशासनिक ऐफिशियेंसी का कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे आर्थिक ऐफिशियेंसी का कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे रेलवे की कार्यकुशलता का कोई तर्क नहीं है । महोदया, इससे पहले 1983 की जो रेलवे रिफॉर्म कमेटी बनी थी, 1993 की जो रेलवे ऐडवाईज़री कमेटी बनी थी और 1996-97 की जो रेलवे स्टैंडिंग कमेटी थी, तमाम कमेटियों ने बड़ी तल्खी के साथ इस बात को कहा था कि रेलवे के नए जोन बनाने के पीछे कोई नया औचित्य नहीं है ...**(व्यवधान)**... रेलवे स्टैंडिंग कमेटी ने इसका विरोध किया था ...**(व्यवधान)** ...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): आप इनको बोलने दीजिए ...**(व्यवधान)** ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If we take an issue which is complicated, then, this is going to happen. ...(Interruptions)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभापति महोदया, मैं यह कहना चाहूंगी कि वामपंथी पार्टियां कभी भी प्रांतीयतावाद की संकीर्ण राजनीति नहीं करतीं । उनकी राजनीति के सामने हमेशा देश के वृहत्तर हित ही रहते हैं । इसलिए जब हम इस निर्णय का विरोध भी करते हैं, उस समय भी हमने कभी भी इस बात की कोशिश नहीं की कि इस तरह के मुद्दे को प्रांतीयतावाद का मोड़ दिया जाए । इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि इस तरह का जो गंभीर सवाल है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने ...**(व्यवधान)** ...

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बिहार) : जो सवाल ये उठा रही हैं, यह दो प्रांतों के बीच में विभेद पैदा करता है...**(व्यवधान)** ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : विभेद आप पैदा कर रहे हैं ...**(व्यवधान)** ...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): हमें कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली, आपको मालूम है ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. ...(Interruptions)... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Madam, I have to seek some information. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, यह जो "ममता" और "समता" का झगड़ा चल रहा है ...(व्यवधान) ...

उपसभापति : ये प्वाइंट ऑफ इन्फॉरमेशन पूछ रहे हैं ...(व्यवधान) ...

श्री एस.एस. अहुलवालिया : महोदया, क्या सदन में कोई भी ऐसी बहस होनी चाहिए जिससे क्षेत्रीयवाद और राज्यों के बीच विभेद पैदा हो ...(व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : महोदया, ये लोग "ममता" और "समता" के नाम पर देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ...(व्यवधान) ...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदया, यहां ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे क्षेत्रीयवाद और राज्यों के बीच में विभेद पैदा हो ...(व्यवधान) ... इस तरह से राज्यों के बीच में भेदभाव पैदा किया जा रहा है, यह चिंता की बात है ...(व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं, यह खिलवाड़ हम देश के साथ नहीं होने देंगे ...(व्यवधान) ...

SHRI NILOTPAL BASU: This is a hypocritical Government, Madam. ...*(Interruptions)*....

THE DEPUTY THE DEPUTY CHAIRMAN: If all of you are not going to......*(Interruptions)*..... Please sit down......*(Interruptions)*... It is all right ...*(Interruptions)*...Please sit down ...*(Interruptions)*... I think, the CPI(M) Leader should control his Members ...*(Interruptions)*... Please .... *(Interruptions)*... Mr. Roy, I don't understand that when I have permitted her to speak, why are you interrupting her? ...*(Interruptions)*... Please sit down. आपको इजाजत दे दी, भाषण करने की इजाजत नहीं दी थी। I have made a commitment that every Member will speak for two minutes only. Mrs. Maheswari, if you are going to speak beyond that, I can also go beyond that...*(Interruptions)*... बस हो गई बात खत्म आपकी। Now, Shri Pranab Mukherjee.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Madam, Deputy Chairperson, not only this decision is very unfortunate, but the situation is also emotive. I am not going into the merits or demerits of this decision. I am not saying that this side is right or that side is wrong, but, unfortunately, since this matter is almost six-years-old, emotions have risen high. The Legislative Assemblies of two States have passed the Resolutions in this

respect. It was expected that while reiterating its decision, the Union Cabinet will take all factors into account and take an appropriate decision to defuse the tension, and not heighten it. Madam, I do not understand, if the decision was so important - while presenting the Budget, the Railway Minister identified seven areas of priority - it should have found a place in those seven areas of priority, but, it did not happen. This Government came to office in 1998. This decision was taken in 1996. If it had been considered absolutely necessary from the operational point of view, for improving the efficiency of the Railways, for strengthening the financial position of the Railways, one would have legitimately expected that in the Budget of 1st year or 2nd year or 3rd year. But instead of making some allocations, as a routine matter, in the Railway Budget, no effective step was taken for implementing this decision. I am not against it or I am not in favour of it. What I am respectfully submitting, through you, to the Leader of the House and representative of the Government is that when emotions have risen high, when, unfortunately, a position has been taken by most of the political parties, representing the concerned States,- not one or two States are involved, but a large number of States are involved - let the Government consider it dispassionately, have an indepth discussion with the Chief Ministers of the States concerned, let this House be also taken into confidence, let the Railway Minister come and explain how this bifurcation is going to help Railways operationally, financially and in improving the efficiency of the Railways. With these words, most respectfully, I submit that when there is a fire, please don't put a litre of petrol, please try to put a bucket of water and extinguish the fire. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is exactly what I am trying to do in this House, atleast. Every State has its own viewpoint. Bihar has its own viewpoint. One of the hon. Members was very angry. He has his own point of view. I don't mind one hon. Member speaking from Bihar and another Member speaking from Orissa.

AN HON. MEMBER: Madam,...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you to speak...(*Interruptions*)... I am afraid, it may not become an issue in Maharashtra also...(*Interruptions*)...

प्रो0 रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम्, इस मामले से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है जिसके बारे में किसी ने नहीं कहा। हमारा गोरखपुर जोन बिना खत्म किए हुए खत्म कर दिया गया है। उसके दो डिवीजन सोनपुर और समस्तीपुर हाजीपुर में चले गए,

बनारस इलाहाबाद में चला गया। Now, Gorakhpur is the only Railway Zone in India which has no divisional headquarter. अब गोरखपुर जोन बिना खत्म हुए खत्म हो गया। जिनको एतराज होना चाहिए था वह तो चुप बैठे हुए हैं क्योंकि वे प्रधान मंत्री बन गए। यह प्रधान मंत्री का झुनझुना हर बार उत्तर प्रदेश को दे दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। इसलिए मेरा सीरियस सजेशन है कि उस पर पुनर्विचार होना चाहिए और कम से कम समस्तीपुर और जौनपुर में से एक डिवीजन तो बना रहना चाहिए जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक गोरखपुर जोन बना रहे। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No; please sit down. ...(Interruptions)... Shri Dinesh Trivedi.

SHRI DINESH TRIVEDI (West Bengal): Madam, as promised, I will not take more than minute-and-a-half. I totally agree with whatever hon. Pranabbabu has said, and our sentiments are the same. Just 15 days before the Parliament Session, I do not know what was so urgent that the hon. Minister for Railways had to decide on such an important issue, which we have seen in this House, has already divided the States. Madam, Indian Railways is Indian Railways. My request is, whatever is good for the Indian Railways, please do that. Do not consider Bihar or Assam or Bengal in this regard and please do whatever is good for the Indian Railways. All the Expert Committees, including the Planning Commission, the CAG, the Rakesh Mohan Committee, and every other Committee, and even seven retired Chairmen of the Railway Board have all rejected and written to the Prime Minister " If you implement this notification, you will not only disintegrate the Railways, but you will disintegrate the entire railway system. So, please re-consider this. Otherwise, we are in for a very, very dangerous time. Thank you, very much Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I do not think, the country can be disintegrated. I am sorry. ...*(Interruptions)*... Yes; I will allow you, Shri Shankar Roy Chowdhury and one Member from Bihar. ...*(Interruptions)*...

प्रो0 रामदेव भंडारी (बिहार): मैडम, मैं भी बोलना चाहता हूं।

उपसभापति : एक मिनट। मैं आपको अलाऊ कर दूंगी। यह मसला ऐसा नहीं है कि खाली यहां हाउस में बोलने से उसका समाधान हो जायेगा। इसके बारे में मैं सरकार से यह आग्रह करूंगी कि रेल मंत्री जी हाउस में आकर एक्सप्लेन करें। चूंकि यह आपकी अपनी समस्या है, लेफ्ट की अपनी समस्या है, उड़ीसा की अपनी समस्या है और अभी माननीय सदस्य यू0पी0 के बारे में बोल रहे थे, यह पूरे देश की समस्या है। सभी सदस्य इस पर बोलें यह जरूरी नहीं है। जिन्होंने स्पेशल मैंशन दिए हैं, वे न बोल पायें तो यह उचित बात नहीं है। ...**(व्यवधान)** ...

प्रो0 रामदेव भंडारी : मैडम, मैं बोलने के लिए काफी पहले से अंगुली उठा रहा हूं।

उपसभापति : मैं वही करुंगी जो हो चुका है। चलिए। आप संक्षेप में बोलिएगा।

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" (बिहार): मैडम, यह बात सही है कि यह भारतीय रेल से संबंधित मामला है। जब प्रशासनिक एफिसियेंसी बढ़ाने के लिए राज्यों का बंटवारा होता है, जिलों का बंटवारा होता है, अगर उसी तरह से रेलवे का बंटवारा हुआ है तो इसमें राज्यों के बीच में विभेद पैदा करना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इस बात को दर्शाता है कि उस पर किसी विशेष राज्य का अधिपत्य है और यही कारण है कि इन भावनाओं के कारण आज दो राज्यों के बीच में विभेद पैदा हुआ है। हम अपने सभी साथियों से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इस तरह का विभेद पैदा नहीं करें। क्योंकि आज जो हाजीपुर का जोन बना है उस जोन को लेकर विवाद है। प्रणब दा बोल रहे थे कि यह 1997 की कैबिनेट का फैसला है और 1998 में इस फैसले की पुष्टि हुई। उस समय आपके सहयोग से सरकार चल रही थी, उस समय आपने क्यों फैसला होने दिया ? सिर्फ उस समय यह फैसला कार्यान्वित नहीं हो पाया ? इसके बारे में सारे निर्णय आपके सामने हुए । अगर उन्होंने राकेश मोहन कमेटी का टर्म आफ रेफरेंस देखा होता तो उस कमेटी के रेफरेंस में डिवीजन के बंटवारे का कोई टर्म नहीं है। इसलिए महोदया, हमारा कहना है कि जब 1996 में फैसला हुआ तो कटिहार डिवीजन जो बंगाल के क्षेत्र का अधिकतर भाग है, उसको उसमें शामिल किया गया था। लेकिन आज उसका व्यावहारिक पहलू और उसकी व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए नए ढंग से उस जोन के निर्माण का फैसला हुआ है। इसलिए आज हम अपने सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस तरह के विभेद को समाप्त करके जो फैसला सरकार ने किया है, उस फैसले पर सभी लोग अपनी सहमति दें और आगे से इस तरह की बात पर दो राज्यों के बीच में मतभेद पैदा नहीं होने दें तथा इसको समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री जीवन राय : आप बातचीत करके इसको सुलझा लीजिए।

उपसभापति :प्रो0रामदेव भंडारी ।इस पर सभी लोग तो नहीं बोल सकते हैं।

उपसभापति : प्रो0 रामदेव भंडारी । अब इस पर सब नहीं बोल सकते । सब इस पर नहीं बोलेंगे। रामदेव भंडारी जी बिहार के हैं, इसलिए बोल रहे हैं ।

प्रो0 रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे का ज़ोन बनाने के मामले को राज्यों का मामला बनाया जा रहा है । देश के सभी भागों से लगातार डिमांड्स होती हैं, कहीं जोन बनाने की डिमांड होती है, कहीं डिवीजन बनाने की डिमांड होती है और सरकार जब महसूस करती है कि यह डिमांड उचित है तो सरकार जोन बनाती है, डिवीजन बनाती है । इन्होंने जो रेलवे रिफॉर्म्स कमेटी की बात की थी, उन्होंने भी चार ज़ोन बनाने के लिए कहा था । 1996 में 6 जोन बनाने का फैसला हुआ और एक सातवां जोन भी बना । महोदया, कोई जिला बनेगा, कोई राज्य बनेगा, कोई सब डिवीजन बनेगा तो कहीं न कहीं से तो हिस्सा काटना ही पड़ेगा । कल यह भी हो सकता है कि नया ज़ोन बने और जो ज़ोन अभी हाजीपुर में बनने जा रहा है, उसमें से हिस्सा काटा जा सकता है । मैं समझता हूं और हमारे बंगाल के जो माननीय सांसद हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह राज्य का मामला नहीं है । जो जोन बना है, उस ज़ोन को मान लें । हम इनका भी स्वागत करते हैं, ये इसे हृदय

से मान लें । कल हो सकता है कि इसमें से भी कुछ हिस्सा काटकर दूसरी जगह जाए । मैं बंगाल के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह राज्य का मामला नहीं है । पहले हम आपके ही साथ थे । आपसे अलग हुए होंगे तो कुछ तकलीफ आपको हुई ही होगी । उसी तरह से जो नया ज़ोन हाजीपुर का बन रहा है, बंगाल से कुछ हिस्सा काटकर इसमें दिया जा रहा है, तकलीफ की बात तो होगी ही ।

उपसभापति : ठीक है, अब हो गया ।

प्रो0 रामदेव भंडारी : मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसमें तकलीफ करने की बात नहीं है। बिहार भी पहले आपके ही साथ था । इस बात को महसूस करते हुए कि बिहार राज्य देश का एक पिछड़ा हिस्सा है, उस हिस्से को ज़ोन बनने से अगर कुछ लाभ होता है, आपको इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि इस बात को हमारे साथ आप भी सहर्ष स्वीकार करेंगे।

उपसभापति : अब सबका हो गया ।

SHRI DINESH TRIVEDI: Madam, the Government should...

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. You have made your point. I did not like the point that the country is going to disintegrate. I must put the record straight. You may have extreme emotions, but while getting so emotional, you should not say such a thing, that by dividing the zone the country will disintegrate. The country is not going to disintegrate, whether there is railways or no railways. So, don't say such things.

SHRI B.J. PANDA (Orissa): Madam, in a democracy, devolution of authority is a well-understood and often a well accepted concept. It should be no different when it comes to development activities by the Railways. Madam, I will just give one figure to highlight the lack of development of railways in Orissa. The South-Eastern Railways, which is headquartered in West Bengal, has actually, 70 per cent of its lines outside Bengal. A large chunk of this is in Orissa. Thirty per cent of its revenue comes from Orissa. But, when it comes to track development, the the reality is very stark. The national average of track length per thousand square kilometres is 19. But in the case of Orissa it is the lowest at 14. It would not seem so stark; but when you compare it with our neighbouring State, Bengal, which has the highest track length of 42, in the whole country, you would find how backward Orissa is. We have waited for five decades for some of the developments to come to Orissa.

SHRI NILOTPAL BASU: What would you do? Would you uproot

the lines? They are there historically.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He did not interrupt you. So, please do not interrupt him.

SHRI B.J. PANDA: Madam, I would like to point out to the hon. Members that this plan of bifurcation is not to uproot the lines, but to set up an authority where the major portion of the lines exists so that further development projects for which allocations have been made, can actually be implemented. Madam, this development process should go on, and, as you rightly pointed out, it has no bearing whatsoever on the country's integrity. As the hon. Member, Shri Pranab babu, has pointed out, since pressures are being built, there is no reason to submit to those pressures.. It should be a rational decision as to what is good for the country. We should support this, and this must be implemented.

उपसभापति : अभी इतने लोग नहीं बोल सकते हैं । अगर सब लोग बोलने लगेंगे तो पूरी रेलवे पर डिसकशन हो जाएगी । अभी थोड़े दिन बाद रेलवे की डिमांड्स आने वाली हैं, मंत्री जी आपके हाऊस में आएंगे । आपके मन में जो भी दुख है, उसको आप उनके सामने रख सकते हैं ।

उपसभापति : वे ही जवाब दे सकते हैं । यहां न मैं जवाब दे सकती हूं, न ही लीडर ऑफ दि हाऊस जवाब दे सकते हैं ।

श्री सतीश प्रधान (महाराष्ट्र): मानवता की बात उसी समय कर लेंगे मैडम ।

उपसभापति : ठीक है, अब हम रेल से उतर चुके हैं और रेलवे की बात खत्म हो गई है। अभी एक अच्छी बात, drought की बात आप कह रहे हैं लेकिन drought पर तो डिसकशन हो चुका है हाऊस में ।

RE. SEVERE DROUGHT IN ANDHRA PRADESH

डा.अलादी पी.राजकुमार (आंध्र प्रदेश): हो चुका है मगर उसका परिणाम कुछ नहीं मिला । Let me say a few words about it, Madam. मैडम, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे drought पर बोलने का मौका दिया । ...*(Interruptions)*....

THE DEPUTY CHAIRMAN: We will have a discussion. But let us go procedurally.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Andhra Pradesh is reeling under a severe drought. Out of 1100 Mandals, 900 are in the grip of a severe drought. Recently, in the second week of July, our Agriculture Minister has come to Delhi and met the Union Agriculture Minister. He has given a clear